ईरानी कविता / साबिर हक़ा

एक ईरानी कवि हैं साबिर हक़ा। मजदूर हैं। तेहरान में रहते हैं। चूंकि कविता से पेट नहीं भरता, सो पैसे कमाने के लिए ईंट-रोड़ा ढोना पड़ता है। एक इंटरव्यू में साबिर कहते हैं, मैं थका हुआ हूं. बेहद थका हुआ. मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूं. मेरी *माँ* मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मज़दूरी करती थी, मैं तब से ही एक मज़दूर हूं. मैं अपनी *माँ* की थकान महसूस कर सकता हूं. उसकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है. साबिर बताते हैं कि तेहरान में उनके पास सोने की जगह नहीं और कई-कई रातें वह सड़क पर भटकते हुए गुज़ार देते हैं. इसी कारण पिछले बारह साल से उन्हें इतनी तसल्ली नहीं मिल पाई है कि वह अपने उपन्यास को पूरा कर सकें। साबिर 1986 की पैदाइश हैं। अभी तक उनके दो कविता-संग्रह प्रकाशित हैं और ईरान श्रमिक कविता स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पा चुके हैं.

दोस्ती

मैं ईश्वर का दोस्त नहीं हूं
इसका सिर्फ़ एक ही कारण है
जिसकी जड़ें बहुत पुराने अतीत में हैं =
जब छह लोगों का हमारा परिवार
एक तंग कमरे में रहता था
और (ईश्वर) के पास बहुत बड़ा मकान था
जिसमें वह अकेले ही रहता था

बंदूक़

अगर उन्होंने बंदूक़ का आविष्कार न किया होता
तो कितने लोग, दूर से ही,
मारे जाने से बच जाते.
कई सारी चीज़ें आसान हो जातीं.
उन्हें मज़दूरों की ताक़त का अहसास दिलाना भी
कहीं ज़्यादा आसान होता.

घर

मैं पूरी दुनिया के लिए कह सकता हूं यह शब्द
दुनिया के हर देश के लिए कह सकता हूं
मैं आसमान को भी कह सकता हूं
इस ब्रह्मांड की हरेक चीज़ को भी.
लेकिन तेहरान के इस बिना खिड़की वाले किराए के कमरे को
नहीं कह सकता,
मैं इसे घर नहीं कह सकता.

आस्था

मेरे पिता मज़दूर थे
आस्था से भरे हुए इंसान
जब भी वह नमाज़ पढ़ते थे
(अल्लाह) उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था.

ईश्वर

ईश्वर भी एक मज़दूर है
ज़रूर वह वेल्डरों का भी वेल्डर होगा.
शाम की रोशनी में
उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं,
रात उसकी क़मीज़ पर
छेद ही छेद होते हैं.

शहतूत

क्या आपने कभी शहतूत देखा है,
जहां गिरता है, उतनी ज़मीन पर
उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है.
गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं.
मैंने कितने मज़दूरों को देखा है
इमारतों से गिरते हुए,
गिरकर शहतूत बन जाते हुए.

मृत्यु

मेरी मां ने कहा
उसने मृत्यु को देख रखा है
उसके बड़ी-बड़ी घनी मूंछें हैं
और उसकी क़द-काठी,जैसे कोई बौराया हुआ इंसान.
उस रात से
मां की मासूमियत को
मैं शक से देखने लगा हूं.

राजनीति

बड़े-बड़े बदलाव भी
कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं.
हाथ-काम करने वाले मज़दूरों को
राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल देना भी
कितना आसान रहा, है न!
क्रेनें इस बदलाव को उठाती हैं
और सूली तक पहुंचाती हैं.

सरहदें

जैसे कफ़न ढंक देता है लाश को
बर्फ़ भी बहुत सारी चीज़ों को ढंक लेती है.
ढंक लेती है इमारतों के कंकाल को
पेड़ों को, क़ब्रों को सफ़ेद बना देती है
और सिर्फ़ बर्फ़ ही है जो
सरहदों को भी सफ़ेद कर सकती है.

सरकार

कुछ अरसा हुआ
पुलिस मुझे तलाश रही है
मैंने किसी की हत्या नहीं की
मैंने सरकार के ख़िलाफ़ कोई लेख भी नहीं लिखा
सिर्फ़ तुम जानती हो, मेरी प्रियतमा
कि जनता के लिए कितना त्रासद होगा
अगर सरकार महज़ इस कारण मुझसे डरने लगे
कि मैं एक मज़दूर हूं
अगर मैं क्रांतिकारी या बाग़ी होता
तब क्या करते वे?
फिर भी उस लड़के के लिए यह दुनिया
कोई बहुत ज़्यादा बदली नहीं है
जो स्कूल की सारी किताबों के पहले पन्ने पर
अपनी तस्वीर छपी देखना चाहता था.

इकलौता डर

जब मैं मरूंगा
अपने साथ अपनी सारी प्रिय किताबों को ले जाऊंगा
अपनी क़ब्र को भर दूंगा
उन लोगों की तस्वीरों से जिनसे मैंने प्यार किया.
मेरे नये घर में कोई जगह नहीं होगी
भविष्य के प्रति डर के लिए.
मैं लेटा रहूंगा. मैं सिगरेट सुलगाऊंगा
और रोऊंगा उन तमाम औरतों को याद कर
जिन्हें मैं गले लगाना चाहता था.
इन सारी प्रसन्नताओं के बीच भी
एक डर बचा रहता है =
कि एक रोज़, भोरे-भोर,
कोई कंधा झिंझोड़कर जगाएगा मुझे
और बोलेगा
अबे उठ जा सबीर, काम पे चलना है.

एनएचएमः स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सीधी लूट का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा भर में एनएचएम (राष्ट्रीय हैल्थ मिशन) के तहत सेवायें देने वाले करीब दस हज़ार कर्मचारी गत सप्ताह भर से हड़ताल पर हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवा में लगे कुल कर्मचारियों का लगभग एक चौथाई भाग ये एनएचएम कर्मचारी हैं। समझा जा सकता है कि पहले से ही सत्यानाश हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं में से एक चोथाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का अर्थ इन सेवाओं का सवा सत्यानाश हो जाना है। सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं क्योंकि इससे प्रभावित होने वाले आम ग़रीब को यह सरकार कीड़े-मकोड़े से अधिक कुछ नहीं समझती।

यह एनएचएम है क्या और इसे क्यों बनाया गया? देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिन ब दिन बेहाल होता जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के जिम्मे होता है। राज्य सरकार अपने कम संसाधनों का रोना रोकर इस खाते में पर्याप्त धन खर्च नहीं कर पाती। वह बात अलग हैं कि जितना खर्च करती भी है उसका एक बड़ा भाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाता है। देश भर में इन खस्ता हाल सेवाओं को सुधारने के नाम पर सन् 2004 में आई कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के अमेरिका-परस्त सलाहकार मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने पहले एनआरएचएम (राष्ट्रीय ग्रामीण हैल्थ मिशन) फ़िर एनयूएचएम (राष्ट्रीय शहरी हैल्थ मिशन) और अन्त में दोनों को मिला कर एनएचएम बना दिया।

अपनी इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के हालात के अनुरूप उन्हें इस मिशन के लिये भारी अनुदान देना शुरू किया। हरियाणा को भी इसके नाम पर हज़ार से बारह-तेरह सौ करोड़ तक का वार्षिक अनुदान गत 12-13 वर्षों से लगातार मिलता आ रहा है। इतने मोटे अनुदान को सीधे तौर पर राज्य की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत एवं बेहतर करने की अपेक्षा, इस रकम को एनएचएम के माध्यम से खर्च करने की योजना बनाई गयी।

किसी भी सरकारी विभागीय नियमों के विपरीत एनएचएम का सारा कारोबार उचंती खाते में रखा गया। इसका कोई स्थाई स्टाफ़ एवं व्यवस्था कायम करने के बजाय सब कुछ अस्थाई एवं ठेकेदारी प्रथा पर आधारित किया गया। जिस डॉक्टर को प्रारम्भिक वेतन आज 80 हज़ार मिलता है वहीं एनएचएम के डॉक्टर को 20 से 40 हजार। इसी तरह अन्य कर्मचारियों का वेतन भी सरकारी कर्मचारियों का आधा या चौथाई रखा गया।

किसी मजबूरी के चलते सेवानिवृत डॉक्टर एवं बेरोजगारी के चलते युवा वर्ग भी एनएचएम की सेवा में आ लगा। काम करने के लिये इन लोगों को तमाम सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों आदि में लगा दिया गया। बरसों काम करते हुए इन लोगों को यह महसूस होने लगा कि जिस काम के इन्हें दस हज़ार मिलते हैं उसी काम के, पक्के कर्मचारियों को 40 हज़ार मिलते हैं। जाहिर है बरसों तक एक साथ, इतनी भारी वेतन विसंगती के साथ काम करने से असन्तोष तो पैदा होना ही था।

मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंत्री बनने से पूर्व एवं पश्चात यह आश्वासन भी दिया था कि वे शीघ्र ही तमाम एनएचएम स्टाफ़ को पक्की सरकारी नौकरी में ले लेंगे तथा उन्हें भी बराबर वेतन एवं सेवा सुविधायें प्रदान करेंगे। लेकिन साढे तीन साल बीत जाने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो इन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा और जुमलेबाज़ों की सरकार का असली चेहरा देखने को मिला।

महत्वपूर्ण सवाल समझने लायक यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर एनएचएम का यह नाटक किया ही क्यों गया? क्यों नहीं तमाम राज्यों की पहले से ही संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा गया?

आज हरियाणा का स्वास्थ्य सेवा बजट करीब 3000 करोड़ का है। एनएचएम का करीब 1000 करोड़। यदि एनएचएम का अलग ड्रामा खड़ा करने के बजाय इसकी रकम भी राज्य की स्वास्थ्य सेवा में मिला कर उसे 4000 करोड़ कर दिया जाता और उससे सेवाओं को पूरा किया जाता तो परिणाम कहीं बेहतर होते। लेकिन परिणाम बेहतर करना तो किसी सरकार का उद्देश्य है नहीं। यहां तो निशाना लूट-कमाई पर रहता है। एनएचएम में लूट-कमाई किसी भी सरकारी विभाग की अपेक्षा कहीं अधिक और आसान होती है।

सरकारी विभाग में हर सामान को खरीदने का नियम है और उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसकी बरसों बाद भी जांच की जा सकती है। कमी पाई जाने पर किसी न किसी अधिकारी की ज़िम्मेदारी तय की जाती है। सारे खर्च का 'कैग' द्वारा ऑडिट हर वर्ष होता है। दूसरी ओर एनएचएम इस तरह के सभी बंधनों से मुक्त है। यहां जब कोई स्थाई कर्मचारी ही नहीं तो किसी भी काम के लिये किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में स्टॉक रजिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं। ईएसआई के एनएच-3 अस्पताल में एक लावारिस एम्बुलेंस का ढांचा गत दसियों वर्ष से खड़ा है, वह एनएचएम भिवानी से यहां लाई गयी थी; लेकिन वह गाड़ी आज किसी के भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। ऑडिट के नाम पर यहां 'कैग' की बजाय प्राईवेट ऑडिटरों से ऑडिट कराया जाता है, जो अपनी फ़ीस लेकर केवल डकारे गये धन के सही वाऊचर-बिल आदि बनवा कर लगवा देते हैं।

इसी एनएचएम के फ़ंड से एक बड़ा तिमंजिला अस्पताल सेक्टर 3 बल्लबगढ में तथा एक सेक्टर 30 में बना खड़ा है, जिसका बरसों तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ तो बाद में उनमें कुछ दफ़्तर आदि खोल दिये गये। कुल मिला कर एनएचएम के नाम पर सरकार न केवल अपने कर्मचारियों को बेवकूफ़ बना रही है बल्कि जनता को भी धोखा दे रही है। कर्मचारी असंतुष्ट और धक्के खाते मरीज, हरियाणा सरकार का यही हासिल रहने वाला है। गंभीर सवाल यह भी है कि जब लोग़ों का बीमार होना और उनके इलाज के लिये अस्पताल व स्टाफ़ एक स्थाई आवश्यकता है तो यह अस्थाई व ठेकेदारी व्यवस्था का क्या मतलब? सरकार की मूर्खता एवं जनविरोधी नीति का एक नमूना ईएसआई हेल्थ केयर है। इसके लिये राज्य सरकार कम से कम 1200 करोड़ का बजट बना सकती है जिसका 88 प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन को देना होता है। ईएसआई हेल्थ केयर से राज्य की लगभग आधी आबादी कवर होती है। लेकिन हरियाणा सरकार इसके लिये मात्र सवा सौ-डेढ सौ करोड़ का ही बजट बनाती है।

एनएचएम की हड़ताल में जनता त्रस्त, खट्टर सरकार मस्त

फ़रीदाबाद।(म.मो.) खुद को गरीबों का हमदर्द बता कर पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार की असलियत आम जनता के सामने आ गई है। गत चार दिसम्बर से एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के डाक्टरों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिला में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। हड़ताल के कारण गरीब तबके के लोग इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे है। लेकिन इन डाक्टरों और कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के मुकाबले वेतन काफी कम दिया जा रहा है। जबकि काम इन्हें स्थाई कर्मचारियों के बराबर करना पड़ता है। इन्हें स्थाई कर्मचारियों के मुकाबले सुविधाएं भी नाम मात्र को मिल रही हैं। ये कर्मचारी पिछले लम्बे समय से वेतन बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की मांग करते आ रहे हैं।

एनएचएम के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र ने बताया कि वे पिछले लम्बे समय से समान काम समान वेतन की मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार लगातार झूठे वायदे कर उनसे काम लेती रही। अब ज्यादा दवाब बनाने पर सरकार ने वेतन तो बढ़ा दिया लेकिन दरअसल उनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। वेतन में मात्र तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। यानी जिस कर्मचारी को दस हजार रुपये वेतन मिलता था, उसे अब 10 हजार 180 रुपये मिलेंगे। उन्हें स्थाई के मुकाबले वैसे ही वेतन काफी कम मिल रहा है। दूसरी तरफ उन्हें कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता।

एनएचएम डाक्टरों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिला में मौजूद तमाम डिस्पेंसरियों का काम ठप्प पड़ा हुआ है। हड़ताल के बहाने इन डिस्पेंसरियों में काम करने वाले स्थाई डाक्टर और कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे हैं। स्थाई कर्मचारी डिस्पेंसरियों में आने वाले मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। मजबूरी में मरीजों को बीके अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे है। यहां पहले ही मरीजों को किस तरह का इलाज मिलता है, यह किसी से छुपा नहीं है। हड़ताल के कारण अस्पताल की ओपीडी करीब डेढ़ गुणा बढ़ जाने के कारण यहां भी स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई है।

बीके अस्पताल की एम्बुलैंस सेवा में भी एनएचएम के कर्मचारी ही तैनात हैं। हड़ताल के कारण एम्बुलैंस सेवा पूरी तरह ठप्प हो गई है। दिल्ली रेफर होने वाले मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा हैं। हड़ताल के कारण गंभीर रोगियों को निजी एम्बुलैंस के चालकों के हाथों लुटने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली जाने में असमर्थ मरीज निजी अस्पतालों के हाथों लुट रहे हैं।

ऐसा नहीं कि खट्टर सरकार को इस हालत के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन सरकार को गरीब जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। जुमलेबाजी करने वाली सरकार ने अभी तक हड़ताली कर्मचारियों से बात तक करने की जरूरत महसूस नहीं की। सरकार ने पिछले दिनों हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस जारी कर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद अब सरकार नए कर्मचारी भर्ती करने की बात कह कर गरीब जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है।